साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 21 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लैंडफिल साइट पर जमा है 11 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा

जम्मू जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बारे में देश भर के लोगों की यह एक धारणा बनी हुई है कि श्रीनगर एक खूबसूरत, साफ-सुथरा और प्राचीनतम शहर है। पर्यटकों को बस डल झील के आसपास का नजारा ही दिखाया जाता है लेकिन किसी को भी इस तथ्य का इल्म नहीं है कि श्रीनगर एक कचरे से भरा हुआ शहर है। यह बात श्रीनगर के सैदापोरा क्षेत्र के स्थानीय निवासी वाहिद अहमद ने डाउन टू अर्थ से कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मियों के महीनों में लैंडफिल साइट से निकलने वाली बदबू 7 से 8 किलोमीटर दूर तक फैलती है।

यह बात श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सामने आई है कि श्रीनगर शहर में अवैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ सालों से लगातार अचन-सैदापोरा (श्रीनगर) के निवासी लैंडफिल साइट को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसे 35 साल पहले वेटलैंड क्षेत्र बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के अचन इलाके में स्थित लैंडफिल साइट पर 11 लाख मीट्रिक टन (एमटी) से अधिक कचरा डाला जाता है और यह 123 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीनगर शहर में प्रतिदिन 600 टन (टीपीडी) ठोस कचरा उत्पन्न होता है और इसमें से 450 टन इसी लैंडफिल साइट पर फेंका जाता है। इस संबंध में मामला 12 दिसंबर 2024 को एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल (न्यायिक सदस्य) और ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) शामिल थे। इस मामले के याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर राहुल चौधरी और इतिशा अवस्थी एनजीटी पीठ के समक्ष पेश हुए। सुनवाई के बाद एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि आयुक्त द्वारा दाखिल रिपोर्ट के अनुसार कचरे का वर्तमान उत्पादन 600 टीपीडी है, जिसके 2028 तक 918.04 टीपीडी बढ़ने का अनुमान है। उक्त दैनिक कचरा उत्पादन में 360 टीपीडी गीला कचरा शामिल है। यह कुल कचरे का 60 प्रतिशत है और 240 टीपीडी सूखा कचरा है, यह कुल कचरे का 40 प्रतिशत है। वर्तमान में श्रीनगर की कचरा निपटान करने की क्षमता अपर्याप्त है। इसकी क्षमता केवल 150 टीपीडी कचरे के निपटन की होती है। इसमें 50 टीपीडी गीला कचरा शामिल है। ध्यान रहे कि श्रीनगर के अचन-सैदापोरा क्षेत्र में अवैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान के लिए इस वर्ष की शुरुआत में एक स्थानीय स्वैच्छिक समूह द्वारा एनजीटी में एक और मामला दायर किया गया। अचन-सैदापोरा के निवासी इस अवैज्ञानिक लैंडफिल साइट को स्थानांतरित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। एनजीटी ने मई 2024 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सीपीसीबी, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की एक संयुक्त समिति का गठन किया। संयुक्त समिति के सदस्यों ने जुलाई 2024 में श्रीनगर में साइट का दौरा किया और हाल ही में एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) की कई खामियां गिनाई गईं हैं। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कई प्रमुख अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों का पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं। प्रतिदिन 100 टन की क्षमता वाला मैकेनिकल सेग्रीगेटर खराब पाया गया, जिससे कर्मचारियों को अकुशल मैनुअल सेग्रीगेशन पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा 120 केएलडी की संयुक्त क्षमता वाले सभी तीन लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट-एलटीपी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही भूजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए बनाए गए बोरवेल भी काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिदिन 130 किलोलीटर की क्षमता वाला एक मल उपचार संयंत्र और एक सेप्टेज उपचार संयंत्र पूरी तरह निष्क्रिय पाए गए। लीचेट संग्रह प्रणालियों की कमी के कारण अनुपचारित लीचेट सीधे लैंडफिल से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित एंकर झील से जुड़े नाले में बहया जा रहा है। इस बीच संयुक्त समिति की रिपोर्ट और श्रीनगर नगर निगम द्वारा दिए गए जवाब का स्वत-संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि हमारा मानना ??है कि ठोस अपशिष्ट, लीचेट मुद्दे या सीवेज समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। अपशिष्ट सीधे नदी में डाला जा रहा है। यह जल अधिनियम 1974 सहित एमएसडब्ल्यू नियमों का उल्लंघन है। इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त को इस विपरित स्थिति को ठीक करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

2024 की सबसे बड़ी जलवायु आपदाओं से 2,000 लोगों की मौत, 288 बिलियन डॉलर का हुआ नुकसान- रिपोर्ट

नई दिल्ली। साल 2024 खत्म इस साल 10 सबसे भयावह जलवायु आपदाओं के कारण दुनिया भर में लगभग 228 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आपदाओं के कारण दुनिया भर में 2,000 से अधिक लोगों की जान चली गई।

दुनिया भर में बड़ी आपदाओं के आर्थिक प्रभाव और मानवीय हताहतों को रिकॉर्ड करने वाली इस रिपोर्ट का शीर्षक % काउंटिंग दि कॉस्ट 2024= अ ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन% है। इस साल दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसे विनाशकारी घटनाओं से अछूता नहीं रहा, लेकिन उत्तरी अमेरिका में चार और यूरोप में हुई तीन घटनाओं ने 10 सबसे महंगी आपदाओं में से सात की जानकारी दी है। शेष तीन चीन, ब्राजील और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में दर्ज की गई हैं।

जलवायु संबंधी इन घटनाओं की गरीब देशों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी, जहां कई लोगों के पास बीमा नहीं है और आंकड़ों की उपलब्धता भी सही नहीं है, आम तौर पर व्यापक सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी अक्सर कम होती है। क्रिश्चियन एड द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान मुख्य रूप से बीमा पर आधारित

नुकसान से संबंधित हैं, जिसका मतलब है कि वास्तविक धन हानि के और भी अधिक होने के आसार हैं। इसलिए रिपोर्ट में केरल के वायनाड में भूस्खलन को सबसे महंगी आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल वायनाड में जुलाई में भयंकर बारिश से संबंधित घटनाओं में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2024 में सबसे बड़ी धन हानि वाली घटनाओं में अमेरिका में अक्टूबर में तूफान मिल्टन के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ, जो 60 बिलियन डॉलर के नुकसान और 25 लोगों की जान लेने वाली सबसे बड़ी अकेली घटना के रूप में सूची में सबसे ऊपर दर्ज की गई है।

वहीं, सितंबर में अमेरिका, क्यूबा और मैक्सिको में आए तूफान हेलेन ने 55 बिलियन डॉलर का नुकसान किया और 232 लोगों की जान ले ली।

2024 में दुनिया के लगभग हर हिस्से में जलवायु संबंधी आपदाएं हुई, चीन में बाढ़ से 15.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और 315 लोगों की मौत हुई। दक्षिण-पश्चिम एशिया में आए तूफान यागी ने 800 से अधिक लोगों की जान ले ली। यागी ने दो सितंबर को फिलीपींस में दस्तक दी, उसके बाद लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड में तबाही मचाई, जहां इसके कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लडिंग या अचानक बाढ़ आई और सैकड़ों हजारों घरों और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी ओर, यूरोपीय देशों में शीर्ष 10 सबसे महंगी आपदाओं में से तीन आपदाएं हुई, जिसमें मध्य यूरोप में तूफान बोरिस और स्पेन और जर्मनी में बाढ़ शामिल हैं, जिसके कारण 13.87 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ और 258 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 226 अक्टूबर में वालेंसिया की बाढ़ में मारे गए। ब्राजील में, रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में बाढ़ से 183 लोगों की मौत हुई और पांच बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में क्रिश्चियन एड के सीईओ पैट्रिक वॉट के हवाले से कहा गया है कि यदि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रक्रिया में तेजी नहीं ले गई, तो ये विनाशकारी जलवायु आपदाएं आने वाले समय के लिए चेतावनी की तरह हैं। वे अनुकूलन उपायों की तत्काल जरूरत को भी सामने लाते हैं, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, जहां संसाधनों की भारी कमी है और लोग चरम मौसम की घटनाओं के प्रति सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उन्होंने आगे कहा कि साल 2025 में सरकारों को चाहिए कि पर्यावरणीय समाधानों में तेजी लाएं, उन्हें उत्सर्जन को कम करने तथा अपने वादों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करते हुए दिखना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु में बदलाव दुनिया पर अलग-अलग तरीकों से असर डालता है तथा इसके सबसे हानिकारक प्रभाव आर्थिक नुकसान के लिए शीर्ष 10 की सूची में दर्ज नहीं होते हैं। इसके अलावा 10 अन्य अहम आपदाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें शायद उतनी सुर्खियां नहीं मिली हों, लेकिन वे दुनिया भर में जीवन को तबाह कर रही हैं।

सरकार की जन हितैषी योजनाओं का मिले सबको लाभ-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विकास के लिए विधायक अपनी विधानसभा का बनाएं मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग की बैठक लेकर दिए निर्देश

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें। जनता के काम समय पर हों, हम सबको इसकी चिंता करनी होगी। इसलिए सभी विधायक अपनी विधानसभा का अगले 5 साल का मास?टर प्लान बनाएं, जिससे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में ग्वालियर एवं चंबल संभाग

की समीक्षा बैठक में वर्चुअली जुड़े स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दोनों संभागों में चल रहे एवं लंबित विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा कर कहा कि निर्माण कार्य तय वक्त पर ही पूरे करें, जिससे आमजन को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी, 2025 तक जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के बजट का केवल 34 प्रतिशत ही खर्च

फसल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की प्रमुख ऑपरेशन ग्रीन्स योजना ने 2024-25 के लिए अपने आवंटित बजट का मात्र 34 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है। यह स्थिति तब है जब महाराष्ट्र में प्याज के किसान भारी नुकसान से लगातार जूझ रहे हैं और पूर्वी राज्यों में आलू की कमी है। यह बात संसदीय रिपोर्ट में कही गई है। ध्यान रहे कि यह योजना इसीलिए बनाई गई थी ताकि किसान और उपभोक्ताओं दोनों लाभ की स्थिति में रहें।

2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय और उपभोक्ताओं द्वारा फसलों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में उनका हिस्सा बढ़ाना था। इसके लिए फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण किया गया जो किसानों को भंडारण सुविधाओं जैसी बेहतर कीमतें मिलने तक माल को स्टोर करने की अनुमति देता है। इसने एक मूल्य श्रृंखला विकसित करने की भी योजना बनाई और शुरुआत में कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए टमाटर, प्याज और आलू पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2021-22 में इस योजना का विस्तार किया गया और इसके अंतगर्त 22 ऐसी फसलों को भी शामिल किया गया, जिनके शीघ्र ही खराब होने का अंदेशा होता है। हालांकि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना की स्थिति अब तक निराशाजनक ही बनी हई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि 11 अक्टूबर 2024 तक आवंटित 173.40 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 59.44 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था जो बजट अनुमान का मात्र 34.27 प्रतिशत ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट का 65.73 प्रतिशत शेष रहने के साथ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (जिसके अंतर्गत यह योजना आती है) को व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करने में संघर्ष करना पड़ सकता है जो तिमाही व्यय सीमा निर्धारित करते हैं। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने के लिए निर्धारित 10 परियोजनाओं में से 14 अक्टूबर 2024 तक केवल तीन ही पूरी हो पाईं थीं। जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष अपनी अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहा है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत अप्रयुक्त निधि और अधूरी परियोजनाएं, इस योजना के प्रभाव और अस्थिर कृषि बाजारों की चुनौतियों का समाधान करने की सरकार की क्षमता पर ही सवाल उठा रही हैं। इस योजना की सीमित सफलता महाराष्ट्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां प्याज के किसान कीमतों में गिरावट से जूझ रहे हैं। प्याज की कीमतों में केवल 15 दिनों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई है जो कि मांग से अधिक आवक के कारण है। किसान विरोध कर रहे हैं और निर्यात को बढ़ावा देने और अपने मार्जिन में सुधार करने के लिए 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क हटाने की मांग कर रहे हैं। पिछले एक साल में सरकार द्वारा किसानों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में की गई कई नीतियों में बदलाव के कारण प्याज उत्पादकों को भारी निराशा है।

दिसंबर 2023 में सरकार ने घरेलू आपूर्ति की कमी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह घरेलू उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। शुरुआत में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाला प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे 4 मई को हटा लिया गया। हालांकि निर्यात शुल्क लगाते हुए 45,884 रुपए प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने से किसानों का मार्जिन और कम हो गया, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया।

भोपाल के विज्ञान मेले में नगरीय विकास विभाग का स्टॉल

प्रदर्शनी में विज्ञान और योजनाओं की दी जा रही है जानकारी

भोपाल भोपाल के जम्बूरी मैदान में विज्ञान भारती एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से आयोजित विज्ञान मेले में बच्चों, युवाओं और नागरिकों को देश-दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही तरक्की की जानकारी आकर्षक मॉडल्स के माध्यम से दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिये विज्ञान मेले में स्टॉल लगाया है। स्टॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मेट्रो, अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी नागरिकों को दी जा रही है। स्टॉल में विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा स्कॉच अवार्ड से पुरस्कृत धर्मपुरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ग्वालियर में निर्मित की गयी कॉलोनी और नगर निगम भोपाल के बॉयो सीएनजी प्लांट सहित भानपुर खंती उद्यान का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल पर मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। विज्ञान मेले का समापन 30 दिसम्बर को दोपहर बाद होगा। विज्ञान मेले की शुरूआत 27 दिसम्बर को हुई थी।

देखरेख की जिम्मेदारी निभाएगी एजेंसी

इंदौर. आइडीए ने करोड़ों रुपए खर्च कर आइएसबीटी कुमेड़ी और सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। दोनों अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। आइडीए के पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए दोनों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा।

आइडीए ने करीब 100 करोड़ खर्च कर आइएसबीटी बनाया है, लेकिन सिर्फ 186 बस संचालक अपनी बसों का संचालन यहां से करने को तैयार हुए हैं। सरवटे बस स्टैंड का संचालन नगर निगम कर रहा है, लेकिन आइएसबीटी का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। आइडीए बोर्ड बैठक में संचालन के लिए एजेंसी तय करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई है। जब तक एजेंसी तय नहीं होती है, तब तक निर्माण एजेंसी संचालन करेगी। यहां बने रेस्टोरेंट व दुकानों की नीलामी आइडीए करेगा। बस संचालकों को यहां से वाहन चलाने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आरटीओ को दी है। आइडीए ने स्कीम नं. 134 में छह मंजिला सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसका संचालन भी अगले महीने से शुरू करने का लक्ष्य है। अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनाई है। यहां 32 फ्लैट हैं। पहले इन्हें बेचने की योजना थी, लेकिन बोर्ड बैठक में किराए पर देने का फैसला हुआ है। संचालन निजी एजेंसी से कराएंगे, जिसे एक महीने में तय करने का टारगेट है। आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक, बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य सीनियर सिटीजन की अच्छी देखभाल करना है। संचालन के लिए जल्द ही एजेंसी तय की जाएगी।

आईआईटी, मद्रास के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम बनाने का खोजा नया तरीका

मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम के निर्माण के लिए एक नई और अनोखे तरीके की खोज की है। यह प्रक्रिया ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और कई अन्य क्षेत्रों के लिए अहम है। इसका उपयोग मजबूत, हल्के और नष्ट न होने वाले मैग्नीशियम कास्टिंग के निर्माण को सक्षम बनाती है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि %स्ट्रेन इंटीग्रेटेड गैस इन्फ्यूजन (एसआईजीआई) कही जाने वाली यह विधि मैग्नीशियम मिश्र धातु कास्टिंग की भीतरी संरचना में सुधार करके, इससे मिलते-जुलते मिश्र धातु के साथ संरचना बनाने, मजबूती को बढ़ाकर, उत्पादन समय और निर्माण लागत दोनों को कम करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। विज्ञप्ति के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीशियम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार समिति से 'वर्ष 2024 की अनोखे प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीशियम पुरस्कार' मिला है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीशियम सोसायटी (आईएमएस) और जर्नल ऑफ मैग्नीशियम एंड अलॉयज (जमा) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली टीम हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रक्रिया को मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के कई ग्रेडों के लिए सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है, जिससे उनकी ताकत, लचीलापन और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार के अनोखे परिणाम सामने आए हैं। पारंपरिक कास्टिंग प्रक्रियाओं की तुलना में, एसआईजीआई प्रक्रिया द्वारा विकसित मैग्नीशियम ए जेड91 कास्टिंग ने ताकत में दो गुना सुधार, लचीलेपन में तीन गुना सुधार और नष्ट न होने में अहम सुधार दिखाया।

शोधकर्ताओं ने अब इस तकनीक को अन्य हल्के पदार्थों, जैसे मैग्नीशियम कंपोजिट और एल्युमीनियम-आधारित मिश्र धातु और कंपोजिट में अपनाने पर काम शुरू किया है, ताकि इसे औद्योगिक उपयोग के लायक बनाया जा सके। यह नए कास्टिंग प्रक्रिया की दक्षता के साथ कंपोजिट बनाने की भी बहुत संभावना है। एसआईजीआई प्रक्रिया द्वारा विकसित सामग्री अधिक मजबूत, अधिक टिकाऊ और इस पर जंग नहीं लग सकता है। इस नए मैग्नीशियम मिश्र धातु कास्टिंग के निर्माण के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। प्रेस विज्ञप्ति में आईआईटी मद्रास की रिसर्च स्कॉलर सुश्री विद्या तिवारी के हवाले से कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में दुनिया भर में हो रहे बदलाव ने ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए हल्के पदार्थों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। मैग्नीशियम मिश्र धातु, जो एल्यूमीनियम की तुलना में दो-तिहाई हल्की और स्टील के वजन का एक-चौथाई है, एक अहम समाधान प्रस्तुत करती है। मैग्नीशियम-कास्ट, मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के सभी प्रयोगों का 80 फीसदी हिस्सा हैं, जिससे उनका विकास आधुनिक उद्योगों के लिए और भी अहम हो जाता है। स्ट्रेन इंटीग्रेटेड गैस इन्फ्यूजन (एसआईजीआई) प्रक्रिया के अहम फायदों में, बेहतर ताकत, लचीलापन और संक्षारण प्रतिरोध के साथ हल्के मैग्नीशियम कास्टिंग का उत्पादन होता है। उत्पादन प्रक्रिया तेजी से होती है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। अतिरिक्त उपचार की जरूरत नहीं होने से निर्माण लागत को कम हो जाती है।

कम ईंधन की खपत करने वाले हल्के वाहनों को सक्षम करके सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। यह ऑटोमोटिव से लेकर एयरोस्पेस क्षेत्रों तक, उत्पादों में मैग्नीशियम मिश्र धातुओं का उपयोग करने के लिए उद्योगों के लिए अवसर खोलता है। विज्ञप्ति के मुताबिक, आईआईटी मद्रास में इनोवेटिव मैटेरियल्स प्रोसेसिंग एंड कैरेक्टराइजेशन रिसर्च ग्रुप (आईएमपीसीआरजी) भी लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सेमी-सॉलिड स्टेट, माइक्रोवेव, थर्मो-मैकेनिकल, फॉर्मिंग, माइक्रो-फॉर्मिंग, सुपरप्लास्टिक फॉर्मिंग और घर्षण आधारित तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नए टिकाऊ निर्माण मार्गों को विकसित करने पर आधारित है, ताकि विभिन्न उत्पाद मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम आधारित कंपोजिट और मिश्र धातु जैसे जटिल सामग्री का निर्माण किया जा सके।

वन-रेलवे ने नहीं गिने पेड़, पटरियां बिछाने में देरी

इंदौर वन विभाग के अफसरों के अनुसार, प्रोजेक्ट में इंदौर वन मंडल का इंदौर से बड़वाह तक का हिस्सा है। इस बीच करीब 15 हजार पेड़ कटने का अनुमान है। इसके बदले रेलवे जमीन व पौधे लगाने के लिए मुआवजा देगा। एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। अभी रेलवे की एजेंसी व वन विभाग पेड़ों की गिनती कर रहा है। इसके बाद ही लाइन बिछाने की अनुमति की प्रक्रिया होगी। करीब 8 माह से अफसर पेड़ ही गिन रहे हैं। इंदौर. इंदौर-खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है। रेलवे को काम शुरू करने के लिए पहले वन विभाग के साथ मिलकर रेल लाइन में बाधक पेड़ों की गिनती करनी है। दोनों विभाग लंबे समय से गिनती में लगे हैं, लेकिन पेड़ों को चिन्हित करने का काम कछुआ चाल से चलने के कारण प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इंदौर से बड़वाह के बीच करीब 15 हजार पेड़ बाधक हैं। मालूम हो, इंदौर के लिए अहम माने जाने रतलाम-महू-खंडवा-अकोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को बजट में 910 करोड़ रुपए मिले हैं। 2008 में इस प्रोजेक्ट को विशेष दर्जा मिला है। इसकी लागत करीब 2 हजार करोड़ है। रेलवे ने पातालपानी से बलवाड़ा तक डायवर्टेड रेल लाइन के 468.65 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे प्रमुख दो बड़ी सुरंगें भी शामिल हैं। इसके पहले 4 किलोमीटर की टनल का टेंडर भी जारी किया जा चुका है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008